an>

Title: Problems faced by fruit industries in Jammu & Kashmir.

सुश्री महबूबा मुफ़्ती (अनन्तनाग) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सदन में हार्टिकल्चर के बारे में इश्यू रेज़ करना चाहती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर की इकोनमी में हार्टिकल्चर रीढ़ की हड्डी है। जब हमारे स्टेट के हालात बहुत खराब रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था एक पूकार से हैंडीकैप्ड हो गई थी, लेकिन हार्टिकल्चर ने ही हमारी स्टेट को जिंदा रखा, खासकर सेब उत्पादन की वजह से। देश में 70 प्रतिशत से ज्यादा सेब की पैदावार जम्मू-कश्मीर में होती है। जब हम सरकार में थे तो हमने इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टोल टैक्स माफ किया था। इसके अलावा हमने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम शुरू की थी। हमने जगह-जगह मंडियां बनाई थीं। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले चार-पांच साल से इस इंडस्ट्री को बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है। आज इसकी हालत यह है कि हमारे कुछ जिलों पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और बड़गाम का कुछ एरिया है, जहां सेब की प्रोडक्शन काफी कम हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फसल में बीमारियां बहुत लग गई हैं। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर और केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत खराब है और वे कॉस्टली भी बहुत हैं। इस कारण पिछले दो साल और इस साल प्रोडक्शन काफी कम हुई है। इस वजह से एप्पल ग्रोअर्स को बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू-कश्मीर स्टेट में सौभाग्य से किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की है और न एप्पल ग्रोअर्स में किसी का हुआ है। अगर केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है और तुरंत शार्ट टर्म और लॉंग टर्म मेजर्स नहीं उठाती है, तो मुझे खतरा है कि खुदा-न-खास्ता, जितना नुकसान उन एप्पल ग्रोअर्स का हो रहा है, जिन्होंने इतने कर्जे ले रखे हैं, उनके साथ कोई हादसा न हो जाए। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से अपील करना चाहती हूं कि वह इसमें तुरंत शार्ट टर्म मेजर्स उठाकर जिन किसानों पर लोन है, केसीसी लोन या दूसरे हैं, उसमें तुरंत हस्तक्षेप करे, नजरसानी करे। इसके अलावा लॉंग टर्म प्रोसेस में जो पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और बड़गाम के एरियाज में ऑर्चर्ड़ बहुत पुराने हो गए हैं, उन्हें रिप्लेस करने की जरूरत है। जब तक वे पेड़ बने होंगे, तब तक उन किसानों को कोई न कोई पैकेज देने की जरूरत है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि अभी सदन में जो भी मंत्री जी बैठे हैं, वे इसे नोट कर लेंगे और कृषि मंत्री जी तक हमारी इस समस्या को पहुंचाएंगे। हमें यह भी उम्मीद है कि इसमें जरूर इंटरवेंशन होगा।